



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan
रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

क	अपील / फाइल नं./ Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/ Date
	V2/4/GDM/2020	08/UrbanRef/19-20	16-12-2019

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-033-2020

आदेश का दिनांक / Date of Order:	05.03.2020	जारी करने की तारीख / Date of issue:	06.03.2020
------------------------------------	------------	--	------------

श्री गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri. Gopi Nath, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s Mehul Geo Projects LLP, Plot No. 455 Ward 3/B Adipur, Gandhidham

इस आदेश (अपील) से व्याथत कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलाय न्यायाधिकरण के प्रांत अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 को धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) बर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में ब्रताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उम शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/-, Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty/demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलाय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 को धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उम शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेन्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, वशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- वशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) **भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :**
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामला में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने में भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
(iv) मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और गेमे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियंत्रित की गई तारीख अथवा ममायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साध्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहां संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पट्टी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने में संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.

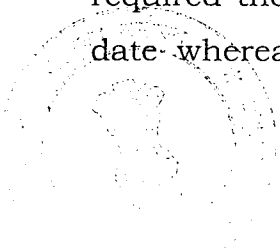
:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s Mehul Geo Projects LLP, Plot No. 455, Ward 3/B, Adipur, Gandhidham (hereinafter referred to as "**Appellant**") filed Appeal No. V2/4/GDM/2020 against Order-in-Original No. 08/UrbanRef/19-20 dated 16.12.2019 (hereinafter referred to as '**impugned order**') passed by the Asst. Commissioner, Central GST & Central Excise, Urban Division, Gandhidham (Kutch)(hereinafter referred to as '**refund sanctioning authority**').

2. The brief facts of the case are that the Appellant had filed a refund claim application dated 18.09.2019 for Rs. 6,15,051/- regarding excess payments made to the Government on account of Service Tax on Works Contract Services for the period from April to June, 2017. The payment has been made by the appellant as per the applicability of Service Tax during the relevant period on Works Contract Service. The refund claim was filed on the ground that reconciliation of books of account with Service Tax returns for the aforesaid period revealed the income reported in the Service Tax returns for the relevant period was higher, resulting in excess payment of Service Tax. The refund sanctioning authority rejected the refund claim on the ground that the refund application filed by the appellant under Section 11 B of the Central Excise Act, 1944 (hereinafter referred to as '**the Act**') was time barred as the same has been filed on 18.09.2019 whereas the appellant has paid the service tax for the period on 24.08.2017. The refund sanctioning authority held that the appellant is not eligible for refund of Rs. 6,15,051/- as the refund claim was neither in accordance with the provisions of Section 70(1) of Finance Act, 1994 nor with the provisions of Section 11 B of the Act and Rules framed thereunder as applicable in the Service Tax matters.

3. Aggrieved, the Appellant has preferred appeal, *inter-alia*, on the following grounds:-

3.1 That the refund claim was rejected on the ground that the provisions of Section 11 B of the Act read with Section 83 of the Finance Act, 1994 required the appellant to file the claim within one year from the relevant date whereas the appellant filed the claim on 18.09.2019 for claiming



refund of Service Tax paid on 24.08.2017, i.e after expiry of one year.

3.2 That the provisions of Section 70(1) of the Finance Act, 1994 is not applicable to the cases involving amount paid under mistake of law; that legal position flowing amongst large number of judicial pronouncements is that where any amount is paid under mistake of law, the same would fall outside the purview of Section 11B of the Act and must be returned.

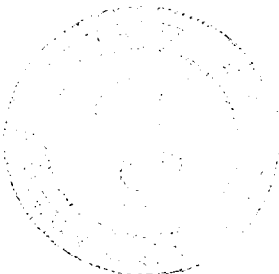
3.3 That they relied upon the case of Commr. of C.Ex. (Appeals), Bangalore Vs KVR Construction, 2012 (26) S.T.R 195 (Kar.) which has been upheld by the Hon'ble Supreme Court.

3.4 That the reference made by the adjudicating authority to the provisions of Section 70(1) of the Finance Act, 1994 and Rule 6(4) of Service Tax Rules, 1994 is extraneous and inapplicable to the facts and circumstances where there is no dispute about excess payment made; that none of the provisions spell out that failure to observe any or all of them would result in automatic and absolute appropriation of the excess amount at the hands of Government, therefore denial of the excess amount is devoid of law and must be quashed and set aside. They have prayed to allow the appeal.

4. In Hearing, Shri Vikas Mehta, consultant appeared on behalf of the appellant and reiterated the submission of appeal memo and also produced additional submissions dated 20.02.2020 and requested to allow the appeal.

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, and written submissions made by the Appellant. The issue to be decided in the present appeal is whether the impugned order rejecting refund claim of Rs. 6,15,051/- is correct, legal and proper or not.

6. On going through the records, I find that the appellant had shown the taxable value under Works Contract Service as Rs. 10,34,87,412/- instead of Rs. 9,32,36,492/- in their Service Tax Return for the period April to June, 2017, owing to which, an excess payment of Rs. 6,15,051/- had taken place for which the appellant had filed a refund application on 18.09.2019. The refund claim was eventually rejected by the refund



sanctioning authority observing that the claim is neither in accordance with provisions of Section 70(1) of the Finance Act, 1994 nor with provisions of Section 11B of the Act and Rules.

7. I find that the appellant has contended that the provisions of Section 70(1) of the Finance Act, 1994 and Rule 6(4) of the Service Tax Rules, 1994 are not applicable to the cases involving amount paid under mistake of law.

In this regard, I observe that the appellant had erroneously paid Service Tax amount of Rs. 6,15,051/- and shown this excess amount of works contract receipt in their ST-3 returns due to arithmetical mistake. I note that the refund sanctioning authority has also not disputed on that. Hence, I find that the provisions of Section 70(1) of the Finance Act, 1994 and Rule 6(4) of the Service Tax Rules, 1994 are not applicable in the instant case.

8. The issue that arises for consideration in this Appeal is, whether the limitation provided for under Section 11B of the Excise Act for claiming refund before the expiry of one year from the relevant date, would be applicable or not to the application filed by the Appellant.

The claim for refund of service tax paid by the Appellant has been rejected for the reason that it was not made before the expiry of one year from the relevant date. I find it would, therefore, be appropriate to reproduce section 11B of the Act, which reads as follows :

SECTION [11B. Claim for refund of [duty and interest, if any, paid on such duty]. —

(1) Any person claiming refund of any [duty of excise and interest, if any, paid on such duty] may make an application for refund of such [duty and interest, if any, paid on such duty] to the [Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise] before the expiry of [one year] [from the relevant date] [[in such form and manner] as may be prescribed and the application shall be accompanied by such documentary or other evidence (including the documents referred to in section 12A) as the applicant may furnish to establish that the amount of [duty of excise and



interest, if any, paid on such duty] in relation to which such refund is claimed was collected from, or paid by, him and the incidence of such [duty and interest, if any, paid on such duty] had not been passed on by him to any other person :

Provided *that where an application for refund has been made before the commencement of the Central Excises and Customs Laws (Amendment) Act, 1991, such application shall be deemed to have been made under this sub-section as amended by the said Act and the same shall be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (2) substituted by that Act :]*

[Provided *further that] the limitation of [one year] shall not apply where any [duty and interest, if any, paid on such duty] has been paid under protest.*

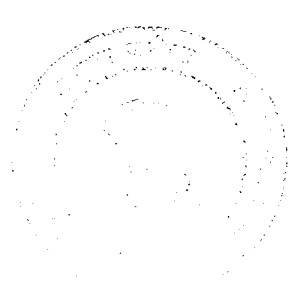
The relevant date has been defined in the Explanation to Section 11B of the Act to mean, amongst others, the date of payment of duty.

8.1 I find that, the Hon'ble High Court of Karnataka in the case of Commissioner of Central Excise (Appeals), Bangalore Vs KVR Construction as reported in 2012(26) S.T.R 195 (Kar.) has observed that, service tax was paid by the assessee under a mistaken notion that it was liable to pay, though it was not liable to pay by virtue of a Circular dated 17 September, 2004 and, accordingly, a refund was sought. The Karnataka High Court examined whether Section 11B of the Act would be applicable if the amount was paid under a mistaken impression that it was liable to be paid. The High Court found that Section 11 B of the Act refers to a claim for refund of duty of excise only and does not refer to any other amount collected without authority of law. Thus, it was held that section 11B of the Excise Act would not be applicable. The relevant observations are as follows :

"18. From the reading of the above Section, it refers to claim for refund of duty of excise only, it does not refer to any other amounts collected without authority of law. In the case on hand, admittedly, the amount sought for as refund was the amount paid under mistaken notion which even according to the department was not liable to be paid."

[Emphasis supplied]

This case was maintained by the Hon'ble Supreme Court in 2018 (14)



GSTL J70. The Supreme Court, on 11th July, 2011, dismissed the Special Leave Petition filed by the Department, against the judgment of the Karnataka High Court.

8.2 I find that the same view was taken by the Hon'ble Madras High Court in M/s 3E Infotech Vs CESTAT, Chennai as reported in 2018(18) G.S.T.L. 410(Mad.) on 28.06.2018 wherein it was observed that :

"13. On an analysis of the precedents cited above, we are of the opinion, that when service tax is paid by mistake a claim for refund cannot be barred by limitation, merely because the period of limitation under Section 11B had expired. Such a position would be contrary to the law laid down by the Hon'ble Apex Court, and therefore we have no hesitation in holding that the claim of the Assessee for a sum of Rs. 4,39,683/- cannot be barred by limitation, and ought to be refunded."

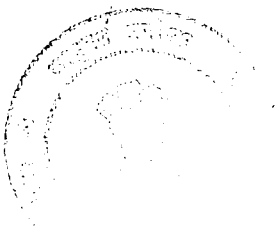
[Emphasis supplied]

8.3 Further, in the case of M/s G.B. Engineers Vs Union of India, the Hon'ble Jharkhand High Court as reported in 2016 (43) S.T.R. 345 (Jhar.) on 06.04.2016 observed that when the amount is not paid under the provisions of the Act or the Finance Act, then if the amount is paid under a mistake, the same cannot be retained by the Government and the provisions of Section 11B of the Act cannot be applied. The observations are as follows:

"9. Section 11B of the Central Excise Act to be read with Section 83 of the Finance Act, 1994 are not applicable to the facts of the present case because, the amount paid by the petitioner is never under the Central Excise Tax nor under the service tax when there is no liability to make the payment of the amount and under the mistake of facts or under mistake of law or under both if any amount is deposited by the assessee, the same cannot be retained by the Union of India under the one or other pretext when a service provider is not liable to make payment of the service tax and if any payment is made, it cannot be covered under Section 11B of the Central Excise Act to be read with Section 83 of the Finance Act, 1994."

[Emphasis supplied]

A



8.4 Further, the Hon'ble Bombay High Court in the case of M/s Parijat Construction Vs Commissioner of Central Excise, Nashik on 13th October, 2017 clearly held that when service tax is paid, even though it is not leviable, the provisions of section 11B of the Excise Act would have no application.

9. Thus, it is clear from the aforesaid decisions that when service tax is not leviable, but it is deposited mistakenly by the Appellant, the provisions of section 11B of the Act relating to limitation would not be applicable. Therefore, the order passed by the refund sanctioning authority cannot be sustained and it is, accordingly set aside.

10. Further, I find that the appellant vide letter dated 18/9/2019 and 04.12.2019 have submitted to the refund sanctioning authority that they have neither carried forward any ITC nor filed Trans-1. The refund sanctioning authority has also not raised any query in this regard.

10.1 I also find that the case laws relied upon by the appellant are squarely applicable to the present case.

11. In view of the above discussion supported by the judicial pronouncements, I set aside the impugned order and allow the appeal of the appellant.

११.१ अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।

11.1 The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सहायक
अधीक्षक (आपिल),
आदिपुर, गांधीधाम,

Gopi Nath
(Gopi Nath)
Commissioner(Appeals)

By R.P.A.D.

To, M/s Mehul Geo Projects LLP, Plot No. 455 Ward 3/B, Adipur, Gandhidham.	सेवा में, मेसर्स मेहुल जियो प्रोजेक्ट्स एल एल पी, प्लॉट नो. 455 वार्ड ३/बी, आदिपुर, गांधीधाम.
---	--

प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम (शहरी) मण्डल, गांधीधाम आयुक्तालय, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल। — ✓

